ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-5* August-2020
Anthology : The Research

एशिया में मोदी की विदेश नीति

Modi's Foreign Policy in Asia

Paper Submission: 12/08/2020, Date of Acceptance: 23/08/2020, Date of Publication: 26/08/2020

सत्येन्द्र कुमार
शोध–छात्र,
विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,
बी.आ.ए.बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

1990 ई. के दशक के बाद से एशिया विश्व राजनीति और प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बन गया है। एशिया की उभरती हुई दो महाशक्तियाँ चीन और भारत हैं। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वही भारत क्रयशक्ति के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मई 2014 ई. में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा भारत की सत्ता संभालने के पश्चात विदेश नीति के मोर्चे पर काफी सक्रियता देखी जा रही है। अपने पहले कार्यकाल के शपथ–ग्रहण समारोह में सार्क सदस्य देशों सहित मॉरिशस को भी आमंत्रित किया गया था और यह संदेश देने का प्रयास किया गया था कि विदेश नीति के मोर्चे पर सर्वप्रथम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में विश्वास और सुदृढ़ता लायी जाये। भारत अपने पड़ोसियों के साथ–साथ विश्व के अन्य देशों–जापान, इराक, रूस, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों के साथ सक्रियता बढ़ाते हुए विदेश नीति को धार देने का हर संभव प्रयास किया। मजबूत विदेश नीति का परिणाम है कि आज भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चे पर मुकाबला करने में सक्षम प्रतीत हो रहा है। आशियान देशों के साथ मोदी 'लुक इस्ट पॉलिसी' के जगह 'एक्ट इस्ट पॉलिसी' का रूप देकर, साथ ही दक्षिण चीन सागर में वियतनाम और फिलीपींस को समर्थन देकर एक सफल विदेश नीति की परिचय दिया है। खाड़ी देशों के साथ भी भारत के संबंधों में तीव्र विकास हुआ है। वही अमेरिका इरान के बीच मतभेद ने भारत को भी प्रभावित किया है। भारत अपने सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ चतुष्कोणिय संधि किया है। दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को विदेश नीति के मोर्चे पर असफलता भी हाथ लगी है। भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध तो पहले से ही कटुतापूर्ण था अब इसमें और अधिक विस्तार हुआ है। नेपाल, श्रीलंका एवं वर्तमान में बंगलादेश के साथ भारत के संबंध कमजोर हुए है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा जोरों पर है। वही ऐतिहासिक रूप से विश्वासपात्र रूस भारत से कन्नी काट रहा है। इसके अलावे कश्मीर मुद्दे पर तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर आँखे दिखा रहा है।

Asia has become the center of world politics and competition since the 1990s. The two emerging superpowers of Asia are China and India. China is the second largest economy in the world, India is the third largest economy in the world by purchasing power. After Prime Minister Narendra Modi assumed power in India in May 2014, there is a lot of activism on the foreign policy front. Mauritius, including the SAARC member countries, was also invited to the swearing-in ceremony of its first term and an attempt was made to convey the message that on the foreign policy front, confidence and strength in relations with neighboring countries should be first brought. India along with its neighbors and other countries of the world - Japan, Iraq, Russia, China, South East Asia etc., has made every effort to give an edge to foreign policy by increasing its activism. The result of strong foreign policy is that today India seems to be able to compete on both the China and Pakistan front simultaneously. With Asian countries, Modi has introduced a successful foreign policy by replacing 'Look East Policy' as 'Act East Policy', as well as supporting Vietnam and the Philippines in the South China Sea. India's relations with the Gulf countries have also grown rapidly. The same differences between America Iran have also affected India. India has entered into a quadrilateral treaty with Australia, the US and Japan to safeguard its strategic interests. On the other hand, Prime Minister Modi has also suffered a failure on the foreign policy front. India's relationship with Pakistan was already bitter, now it has expanded further. India's relations with Nepal, Sri Lanka and present-day Bangladesh have weakened. Competition with China is in full swing. The same historically confidant Russia is cutting off Cannis from India. Apart from this, Turkey is also showing eyes on the Kashmir issue with Pakistan.

मुख्य शब्द : सुपर पावर, विदेश नीति, पड़ोस पहले, अर्थव्यवस्था, निवेश, तनाव, कुटनीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी।

Super Power, Foreign Policy, Neighborhood First, Economy, Investment, Tension, Diplomacy, Act East Policy.

प्रस्तावना

भारतीय विदेश नीति में 1914 के बाद अहम पड़ाव देखने को मिल रहा है। किसी भी देश की सत्ता में जब नई पार्टियाँ आती है तो उनकी विचारधारा का प्रभाव विदेश नीति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। लेकिन स्थापित विदेश नीति पर आमूल–चूल परिवर्तन करना असंभव होता है, इसका सबसे बड़ा कारण अंतराष्ट्रीय परिदृश्य होता है, वे पुराने नक्शे कदम पर एवं राष्ट्रहित में ही विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं। मई 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आयी जिसने अपने शपथ ग्रहण समारोह में 'पड़ोस पहले' की नीति का अवलंबन करते हुए दक्षेस देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। इसमें उन्होंने संकेत देने का प्रयास किया कि आने वाले समय में हमारे विदेश नीति की रूप–रेखा क्या होगी? मोदी ने दूसरे दिन कार्यालय में दक्षिण एशियाई देशों के उन सभी प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय वार्ता की जिसे मीडिया ने मीनी सार्क सम्मेलन का नाम दिया। बाद में इसरों में एक लॉंच समारोह के दौरान उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों से कहा कि दक्षिण एशिया के लोगों के टेलीमेडिसीन एवं इ–लर्निंग आदि जैसे प्रौद्योगिकी के फल को साझा करने के लिए वर्तमान में इस क्षेत्र में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, कार्यक्रम के लिए कार्यरत उपग्रह के पूरक के लिए एक समर्पित सार्क उपग्रह–2 विकसित करने का प्रयास करें।[1]

'पड़ोस पहले' की नीति अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने सबसे छोटे पड़ोसी देश को तरजीह देते हुए पहली अधिकाधिक विदेश यात्रा की शुरूआत भूटान से की और भारत–भूटान के सम्बन्धों को एक नई ऊँचाई देने का प्रयास किया 'पड़ोसी पहले' नामक दृष्टिकोण भारत सरकार द्वारा अपनाया गया एक वाक्यांश चार चीजों को दर्शाता है– पहली, नई दिल्ली की तात्कालीन पड़ोसियों और हिन्द महासागर द्वीप राज्यों की राजनीति और राजनयिक प्राथमिकता देने की इच्छा है। दूसरी, पड़ोसियों को संसाधनों उपकरणों और प्रशिक्षण के रूप में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना है। तीसरी, अधिक से अधिक कनेक्टिवीटी और एकीकरण ताकि लोगों, माल, ऊर्जा, पूंजी और सूचना के मुक्त प्रवाह में सुधार हो सके। चौथी, भारत अगुआयी में क्षेत्रीयवाद के एक मॉडल को बढ़ावा देना है जिसके साथ पड़ोसी सुविधाजनक महसूस करते हैं। 2016 में तात्कालिन विदेश सचिव एस. जयशंकर ने इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट फॉर स्ट्रेटिजिक स्टडीज में भारत, अमेरिका और चीन संबंधों पर कहा था कि आज का भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है न कि बैलेंसिग पावर। उन्होंने यह भी कहा था कि आज भारत बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिये है कि भारत अंतराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की इच्छा और योग्यता रखता है। भारत अब अपनी नई भूमिका हासिल करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। दशकों से हम एक सर्तक विदेश नीति पर चलते आये थे लेकिर 'ग्रेट पावर गेम' में भारत तेजी से कदम बढ़ाने और बड़ी भूमिका पाने के लिए अब तैयार है।[2]

भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंध नीति निरंतर के सबसे सकारात्मक प्रतिनिधि हैं जहाँ मोदी सरकार ने आवामी लीग पर अधिक निर्भरता दिखाई है और तीस्ता नदी विवादों से दूरी बनाए रखी है। साथ ही सीमा एवं भूमि विवाद संबंधी लैंड बॉडर ट्रीटी को अंतिम रूप देने में भी सफलता पायी है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त राष्ट्र के एक न्यायाधिकरण ने विवादित क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बांग्लादेश को देने का फैसला लिया। हाल के समय में RNC और CAA को लेकर दोनों देशों के संबंधों में धुंधलापन अवश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसे भी जल्द ही छँट जाने की संभावना है। मालदीव में अब्दुला यामिन सरकार का भारत के प्रति नाकारात्मक और चीन के प्रति सकारात्मक रूख से भारतीय विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह् अवश्य लगा है लेकिन नशीद समर्पित सरकार आने से भारत के पक्ष में स्थितियाँ बदली हैं।

श्रीलंका के साथ मोदी सरकार के संबंध निश्चित रूप से परम्परा से हट कर थे। राजनीतिक रूप से स्थिर मोदी सरकार ने भारत–श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल समस्या से निकाला। नेपाल में शुरूआती सफलता के बावजूद भूकंप राहत सामग्री एवं संविधान के प्रावधानों को लेकर सम्बन्धों में खटास पैदा हुई है।

नरेन्द्र मोदी कितने भी राष्ट्रवादी हो पर चीन से तनाव व लड़ाई मोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चीन को एक वैश्विक शक्ति उसकी आर्थिक ताकत के कारण माना जाता है। मोदी चाहेंगे की भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। चीन को मोदी से उम्मीद है कि वे दोनों देशों के आर्थिक हितों को बढ़ाने का काम करेंगे। चीन अपने विदेशी निवेश को भारत में बढ़ाने के मौके का इंतजार कर रहा है। चीन अभी भी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। उल्लेखनीय है कि चीन में भी भारत की कई कंपनियाँ निवेश कर रही हैं। नरेन्द्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह है दोनों देशों का सीमा विवाद। चीन–अरूणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है और उसके अलावा भारत के सीमा क्षेत्र में चीनी सैनिक कई बार कैंप लगा चुके है। ब्राजील में दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई थी और शी–जिनपिंग के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता को मोदी ने बेहद सफल करार दिया। इस दौरान सीमा विवाद से लेकर द्विपक्षीय व्यापार और ब्रिक्स बैंक जैसे तमाम मुदों पर बात–चीत हुई। दोनों देश सीमा विवाद से सम्बंधित विवादों को सुलझाने के

लिए 17 दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता कर चुके हैं लेकिन परिणाम सिफर है। भारत का कहना है कि यह विवाद 4057 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ है। वही चीन का दावा है कि यह मात्र अरूणाचल प्रदेश के 2000 किलोमीटर क्षेत्र तक सीमित है जिसे वह दक्षिणी तिब्बत बताता है।[3]

ऊर्जा स्रोतों के माध्मय ने समुद्री कूटनीति और रणनीतिक मामलों को काफी दिलचस्प बना दिया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में प्राकृतिक तेल और गैस की भारी जमाराशि है। चीन में बहुत कम ऊर्जा के स्वदेशी स्रोत हैं और इस प्रकार यह अन्य देशों से अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को आयात करता है। चीन विश्व शक्ति बनना चाहता है। यही कारण है कि चीन ने कृत्रिम द्वीपों को बनाकर समुद्रों पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ जापान ऊर्जा के मामले में काफी कमजोर है और यह काफी हद तक ऊर्जा के लिए परमाणु उर्जा पर निर्भर है। दक्षिण चीन सागर पर अधिकारिता के सम्बन्ध में मध्यस्थता के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हाल के फैसले में इन पानी (समुद्री पानी) पर चीनी दावे को खारिज कर दिया। वियतनाम और फिलीपिंस जैसे कई छोटे देश इन समुद्रों पर अपने वैध अधिकारों पर जोर देने के लिए सहायता और सहयोग के लिए भारत की ओर देख रहे है। इन विवादित समुद्रों पर भारत का रूख स्पष्ट है जो अक्टूबर 2010 में हनोई, वियतनाम में पहले एशियान प्लान के रक्षा मंत्रियों के बैठक में तात्कालीन रक्षा मंत्री ए.के.ऐटनी के सम्बोधन से स्पष्ट है। ई.एस/एस.सी.एस. विवाद पर भारत का पक्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन (यू.एल.सी.एल.ओ. एस.) और सम्बंधित पक्षों के विचारों तथा पूर्व सागर में दलों के आचरण पर घोषणा के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए समर्थन कर रहा है। हिन्द महासागर में पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर बंदरगाह विकसित करने की इजाजत दी, जिससे हार्मुज की तराई के करीब अरब सागर में इसकी मौजूदगी सुनिश्चित हो गई। चीन म्यांमार पहुँचकर म्यांमार के अंडमान सागर में 1992 में को–को आइलैंड को चीन को जाहिर तौर पर निगरानी उपकरणों की स्थापना और सैन्य उपयोग के लिए किराए पर दे दिया था। भारत की देरी के चलते हम्बनटोटा पोर्ट हाथों से निकल गया। उत्तर पश्चिम अरब सागर से पूर्वोतर बंगाल की खाड़ी तक घेरेबंदी की मेखला के रूप में 'मोतियों की माला' रणनीति की चीनी रणनीति की महत्वाकांक्षा को समझना जटिल है।

हिन्द महासागर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महत्व यद्यपि भारत और चीन दोनों के लिए समान दिख रहे हैं। लेकिन कुछ असमानताएँ भी हैं, क्योंकि चीन सामरिक मामलों के लिए इन जल में दिखता है। जबकि भारत रणनीतिक और आर्थिक महत्व दोनों का पालन करता है। चीन द्वारा निर्मित ग्वादर पोर्ट का मुकाबल करने के लिए भारत ने ईरान के चाबाहार बंदरगाह को सफलतापूर्वक बना दिया है। भारत चाबाहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान में एक जहाज का पूरा भार भेज दिया है। इसी तरह भारत और अमेरिका सीइपीईसी के खिलाफ यूरोप और अन्य देशों के लिए सड़क मार्ग की कोशिश कर रहा है। प्रतिक्रियास्वरूप चीन ने एन.एस.जी. में भारत के प्रवेश को अवरोधित किया। चीन पाकिस्तान के दो आतंकी नेता मसूद अजहर और हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अवरोध उत्पन्न कर पाक को सहयोग कर रहा है। हाल के दिनों में भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी ताकत को मजबूत कर, अरूणाचल में सुखोई युद्धक विमानों को भेजकर और लद्दाख में टैंकों की संख्या बढ़ा कर चीन का प्रबल विरोध कर रहा है। डोकलाम के बाद की कूटनीति भारत के पक्ष में स्पष्ट रूप से रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति में निरंतरता रही है क्योंकि भूटान के साथ अपनी विदेश यात्रा शुरू की थी। उनकी विचारशील और दूरदर्शी शुरूआत डोकलाम में परिणाम बनकर सामने आया। हिमालय क्षेत्र का महत्व एजेन्डो में ऊपर है। वाजपेयी शासन के दौरान 1997 से 2004 तक की अपनी विदेश नीति के पहले चरण को आगे बढ़ाया है। डोकलाम गतिरोध के दौरान चीनी मीडिया ने न केवल भारत पर दोष ही नहीं मढ़ा बल्कि भविष्य में परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। अमेरिकी मीडिया में भी इस गतिरोध पर बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई। पूरे यूरोप और एशिया ने 72 दिनों तक विभिन्न अटकलों वाली प्रतियोगिता दिखी।[4]

भारत–जापान संबंधों के मामले में वर्ष 2000 में 21वी सदी में जापान–भारत ग्लोबल साझेदारी शुरू की गई थी, जापान आज भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का चौथा सबसे बड़ा प्रदाता है। दोनों देशों के पास एक सुरक्षा समझौता के रूप में दोस्ताना सैन्य गठजोड़ भी है जिस पर 22 अक्टूबर 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की अपनी तीन दिन की यात्रा पर अपने समकक्ष शिन्जोआवे के साथ 2016 में एक असैन्य परमाणु करार सम्पन्न किया।[5] भारत–अमेरिका–जापान गठबंधन अनेक मोर्चे पर काम कर रहा है। अमेरिका भारत का अफगानिस्तान में मुख्य भूमिका का समर्थन करता है। दक्षिण चीन सागर में भी तीनों देश साथ–साथ चलने के लिए भी काम कर रहे हैं। जहाँ चीन का तरीका तानाशाही वाला है। चीन फिलिपींस को अपने निवेश और सैन्य शक्ति के बल पर प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। चीन अपने चेकबुक कुटनीति के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में सक्रिय है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने बंगाल की खाड़ी में अपना 10 दिवसीय मालावार 2017 में नौसैनिक अभ्यास पुरा किया था। जबकि उसी समय अमेरिका ने भारत को 365 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य परिवहन विमान की बिक्री की मंजूदी दे दी थी और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले एक निगरानी ड्रोन के लिए भी सौदा किया है।[6]

भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया चारों देशों ने दक्षिण चीन सागर में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए चतुष्कोणियें समझौता किया है। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जल्दी ही एकमात्र सक्षम जीवित सुपर पावर के रूप में खुद को प्रस्तुत किया जो अकेले ही कार्यवाही करने में सक्षम था।

इसके जवाब में भारत रूस और चीनी ने मिलकर ब्रिक्स का निर्माण किया था। अब चीन की एकपक्षीयता पर जोर देने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ एक मंच पर है।[7]

13 नवम्बर 2014 को म्यामार की राजधानी न्यापिइंता में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छह महीन पहले कार्यालय में प्रवेश करने के साथ मेरी सरकार ने हमारी 'पूर्व की ओर देखों नीति' (लुक इस्ट पॉलिसी) को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बड़ी तेजी से और प्राथमिकता के साथ बदला है। उन्होंने शिखर सम्मेलन को नई नीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वर्णित किया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की अन्य कोई मंच वैश्विक आबादी, युवाओं, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के इतने बड़े सामूहिक भारत को नहीं लाता और नहीं कोई अन्य मंच एशिया प्रशांत और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए इतना महत्वपूर्ण है।[8]

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियाँ, प्राथमिकताएँ, औधोगिकीकरण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में भारत की भागीदारी पर केन्द्रित है। फिर भी उर्जा और पर्यावरणीय प्रश्न इन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक देशों के साथ भारत के घनिष्ठ सहयोग को देखते हुए एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत कुछ देशों की तरह कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से कैप करने या कटौती करने पर सहमत नहीं है। क्योंकि भारत मानता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सारा बोझ गरीबों के कंधों पर नहीं डाला जा सकता है। इसके बजाय यह कहता है कि यह हरित ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करेगा और भारत 2014 में घोषणा किया था कि 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले इसके उत्सर्जन को 35 प्रतिशत के स्तर पर कम करेगा। भारत खुद को जलवायु संरक्षण के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने की कोई जिम्मेदारी नहीं मानता है। पेरिस में दिसम्बर 2015 के जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।[9]

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी की सफल शुरूआत की वैश्विक स्तर पर चर्चा हुई। न्यू डेवलपमेंट बैक की स्थापना के लिए समझौता और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय को बनाने के निर्णय को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई सरकार के लिए प्रमुख उपलब्धि के रूप में माना जाता है। म्यामार, सिंगापुर और वियतनाम के विदेशमंत्री के सम्मेलन में श्रीमति स्वराज के दौरे से भारत के पूर्व के साथ सम्बन्धों को लुक इस्ट से एक्ट ईस्ट तक पहुँचा दिया है।[10]

शीतयुद्ध काल में भारत और सोवियत संघ रूस के बीच काफी घनिष्ठता थी। यह घनिष्ठता 1991 ई. में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उत्तराधिकारी रूस से आज तक बनी रही। रूस आज भी भारत का प्रमुख शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश है और मोदी इस रिश्ते में बदलाव नहीं लाना चाहते है। हाल के वर्षो में रूस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ अवश्य रहा है फिर भी मोदी ने अमेरिका के नाराजगी के बाद भी रूस से अक्टूबर 2018 में 36000 करोड़ का एस–400 मिशाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा किया है जो अमेरिका के दबाव की कूटनीति के पश्चात एक निडर और मजबूत विदेश नीति का परिचायक है।

मोदी के नेतृत्व में भारत–इजराइल संबंधों में भी काफी प्रगाढ़ता आई है। मोदी दो बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं इस दौरे के दौरान अधिक आर्थिक सहयोग और आतंकवाद पर खुफिया जानकारी सझा करने, अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन की खरीदारी सहित कई मुद्दों पर समझौता हुआ है। मध्य एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को इस आधार पर भी देखा जा सकता है कि हाल के वर्षो में मोदी की सउदी अरब यात्रा भारत सउदी संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझी जा रही है। सम्बंधों में आयी गर्माहट के मध्य ही सउदी शासन की स्वामित्व वाली सउदी अरामको कंपनी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के 25 प्रतिशत शेयर खरीदने जा रही है। यदि यह डील सम्पन्न हो जाती है तो सउदी अरब का भारत में यह सबसे बड़ा निवेश होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले दो दशकों में भारत सउदी संबंध उतार–चढ़ाव के दौर से गुजरे है, इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान तथा सउदी अरब का इस्लाम के प्रति अत्यधिक झुकाव माना जाता है।[11]

इंडिया एंड ईरान टू ग्रेट सिविलाइजेशंस रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्टस नामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और ईरान हमेशा साझेदार और मित्र रहे हैं। हमारे ऐतिहासिक सम्बंधों ने उतार–चढ़ाव देखे होंगे, परन्तु हमारी साझेदारी हम दोनों के लिए अथक शक्ति का स्रोत रही है। उन्होंने कहा 'समय आ गया है कि हम पारंपरिक संबंधों और सम्पर्को के अतीत के गौरव को फिर हासिल करे'। भारत अपने सामरिक एवं आर्थिक सम्बंधों को मजबूती प्रदान करते हुए चाबाहार बंदरगाह समझौता किया है। लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के कारण भारत के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं जिस कारण वे भारत को उर्जा आपूर्ति में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। चूंकि ईरान से तेल आयात करने वाला भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का 80 प्रतिशत तेल का आयात विदेशों से होता है जिसमें 12 प्रतिशत हिस्सेदारी ईरान की है।[12] भारत और तुर्की के बीच लगातार तनाव साफ नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने लगातार पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद भारत ने कठोरता से आंतरिक मामले से दूर रहने का संदेश दिया। हालांकि पाकिस्तान के साथ तुर्की की दोस्ती यहीं खत्म नहीं हुई और उसने एफ.ए.टी.एफ. में भी पाकिस्तान का समर्थन किया।[13] मई 2015 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा हुई जिसमें मोदी ने कहा कि भारत मंगोलिया के बीच रिश्ते अन्य के खिलाफ प्रतिस्पर्धा से संचालित नहीं है बल्कि यह अथाह साकारात्मक उर्जा पर आधारित संबंध है। इस दौरे में मोदी ने मंगोलिया के साथ एक अरब की आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है जिससे मंगोलिया के आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। मंगोलिया चीन

का पड़ोसी देश होने के कारण भी यह एक कूटनीतिक दौरा माना जा सकता है।[14]

निष्कर्ष

मोदी युग में भारतीय विदेश नीति तीव्र सक्रियता से गुजर रही है। खासकर एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। इस काल में विदेश नीति में तो कोई बहुत परिवर्तन नजर नहीं आया है लेकिन सशक्त, मजबूत एवं तीव्र विदेश नीति ने भारत को एशिया में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी शुरूआती दिनों में 'पड़ोस पहले' की नीति में सफलता अवश्य नजर आयी लेकिन बाद के दिनों में पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और अंततः बांग्लादेश से हमारे सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गए। आतंकवाद के मुद्दे को जोर–शोर से उठाया गया और पाक को अलग–थलग करने का प्रयास किया गया। एक बड़ी सफलता हमें उस समय अवश्य मिली जब डोकलाम में चीन के द्वारा सड़क निर्माण के क्रम में समस्या उत्पन्न हुई। उस समय मोदी ने सशक्त एवं मजबूत विदेश नीति का परिचय देते हुए चीन को अपना पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। जिस कारण भारतीय विदेश नीति के प्रति विश्व के नजरिए में परिर्त्तन आया है। इस क्रम में मोदी द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए अप्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए अधिकांश एशियाई देशों का दौरा किया गया लेकिन कुछ सफलताओं को छोड़ दिया जाय तो व्यापक पैमाने पर असफलता ही हाथ लगी। इन वर्षो में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में विकास जरूर देखने को मिला और 1990 के दशक में अपनायी गई 'लुक ईस्ट पॉलिसी' की जगह 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' ने ले लिया। मध्य एशिया में तुर्की को छोड़ कर अन्य देशों के साथ सम्बन्धों में मजबूती अवश्य आयी है। लेकिन कही न कही अमेरिका–ईरान के बीच तनाव पर हमारी चुप्पी रूस के साथ एस–400 मिशाईल डिफेंस सिस्टम समझौते के मुकाबले स्पष्ट नजर आयी। सामरिक एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिन्द महासागर चर्चा का केन्द्र बिन्दु रहा और इसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली। हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन और क्वाड जैसे संगठनों ने भारतीय विदेश नीति को धार दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मोदी युग में भारतीय विदेश नीति में सक्रियता और मजबूती जरूर नजर आयी। लेकिन व्यापक सफलता का इंतजार अब भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ. चंचल कुमार, प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति, वर्ल्ड फोकस, फरवरी 2018।*
2. *हर्ष वी. पंत, 6 अगस्त, 2019, ओ. आर.एफ ¼ORF½ ¼orfonline.org½*
3. *M.hindi.webdunia.com*
4. *प्रो. सतीश कुमार और प्रतीक कुमार सिंह, नरेन्द्र मोदी और शी–जिनपिंग के जरिए भारत–चीन सम्बंध, वर्ल्ड फोकस, फरवरी 2018*
5. *हरमीत सिंह, भारतीय विदेशीनति की रूपरेखा, वर्ल्ड फोकस, फरवरी, 2018*
6. *प्रो. सतीश कुमार और प्रतीक सिंह, नरेन्द्र मोदी और शी–जिनपिंग के जरिए भारत–चीन सम्बन्ध, वर्ल्ड फोकस, फरवरी, 2018*
7. *मोहन, सी.राजा, इंडियन एक्सप्रेस : 14 नवम्बर 2017*
8. *द हिन्दू: 13 नवम्बर 2014*
9. *प्रो0 नरोत्तमगान और बनिता महनंदिया पेरिस जलवायु सम्मेलन और भारत की नीति पर प्रभाव, वर्ल्ड फोकस, फरवरी 2018*
10. *डॉ. चंचल कुमार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति, वर्ल्ड फोकस, फरवरी 2018*
11. *drishtiias.com/hindi/substance-across-thec-arbiom-sea*
12. *khabar.ndtv.com./new/world/tir*
13. *navbharatimes.com*
14. *m.aajtak.in*